मेहनतकशों का पैग़ाम

मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

पाक्षिक

Email : mazdoormorcha@yahoo.co.in
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

केजरीवाल- सिर्फ मुख्यमंत्री या भावी प्रधानमंत्री — 3
एन आई टी में जुआ सट्टा व सूदखोरी नहीं थम रही

दिल्ली में मोदी को केजरीवल की कड़ी चुनौती — 5

मोहन भागवत जी! देश की जनता आपकी समपत्ति नहीं, आप देश की जनता पर बोझ हैं — 6

16 लाख मज़दूरों को किस गुनाह की सज़ा दे रहा है ई एस आई निगम — 8

वर्ष 28 अंक 6 फरीदाबाद, रविवार, 1-15 फरवरी 2015 फोन : - 9999595632 2 ₹

पांच साल केजरीवाल या मोदी-बेदी की खड़ताल

सरकार नहीं लोकतन्त्र है दांव पर

चुनाव पंडितों की दिल्ली चुनाव को लेकर अपनी-अपनी भविष्यवाणियां हैं। इसी तरह भाजपा, आप और कांग्रेस की ओर से भी अपनी-अपनी जीत के बढ-चढ कर दावे किये जा रहे हैं। यदि इस चुनाव को भारतीय लोकतंत्र के स्वास्थ्य का लिटमस टेस्ट मान लिया जाय तो एक ही पार्टी विजय की हकदार है। वह है 'आप' जो भाजपा और कांग्रेस की पुरानी खड़ताल से भिन्न, नई राजनीतिक भाषा बोल रही है।

मज़दूर मोर्चा, दिल्ली ब्यूरो

दिल्ली में किसी को यह बताने की जरूरत नहीं कि अगर भाजपा और मोदी-शाह के दिलो-दिमाग़ पर केजरीवाल के 49 दिन के शासन का भूत न सवार होता तो न तो उन्हें किरण बेदी को अपना तुरूप का पत्ता बनाना पड़ता और न ही भ्रष्टाचार, बिजली दर, मुफ्त पानी, रोज़गार, मंहगाई जैसे जनमुद्दों को बढ-चढ़ कर अपनाना पड़ता। उस हालत में भाजपा का काम महज कांग्रेस और शीला दीक्षित के 15 वर्ष के शासन की कमियां गिनाने से चल जाता। तब, अन्य राज्यों की तरह दिल्ली में भी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने की जरूरत भाजपा को नहीं पड़ती। चुनाव उपरांत मोदी जिस पर ऊंगली रखते, वह दिल्ली का मुख्यमंत्री हो जाता।

किरण बेदी को तुरुप के पत्ते की तरह लाया तो जरूर गया है पर बाज़ी फ़िर भी आसान नज़र नहीं आती। ऐसा इस लिये क्योंकि 'आप' पार्टी के 49 दिन के छोटे से शासनकाल में ही दिल्ली की जनता का एक भिन्न तरह की रीजनीति से सुखद साक्षात्कार हुआ। इस दौरान मन्त्रियों और विधायकों की चिरपरिचित लूट नदारद रही। यही नहीं वे सभी बढ-चढ कर जनता को घूसखोरी और महंगाई से निजात दिलाने में लगे रहे। यही नहीं, इस सरकार ने चुनाव पूर्व के अपने वायदों को पूरा करने में जैसी तेजी दिखाई वह अभूतपूर्व थी।

जनता ने हमेशा ही सत्ता और पूंजी के याराने का नंगा नाच देखा है। 'आप' पार्टी के शासन में यह समीकरण भी उलट गया। सरकार ने मुनाफ़ाखोर बिजली कम्पनियां पर तो लगाम कसी ही, जिससे बिजली दरें आधी करने में मदद मिली। साथ ही अम्बानी और कांग्रेसी तेल मंत्री मोइली की मिलीभगत से गैस के दाम जो चौगुणे किये जा रहे थे, उन्हें एक आपराधिक मुकदमा दर्ज करके निशाने पर ले लिया। ध्यान रहे कि गैस के दाम को बढाने के प्रस्ताव को बतौर मुख्यमंत्री गुजरात नरेन्द्र मोदी का भी समर्थन था। क्या दिल्ली का आम नागरिक केजरीवाल व उनके सहयोगियों के इन कदमों को यूं ही भूल सकता है? राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कयास है कि दिल्ली चुनाव के बाद मोदी सरकार का कार्पोरेट चेहरा पूरी तरह सामने आ जायेगा। जाहिर है, कार्पोरेट मुनाफ़ा जनता की कीमत पर ही फलना-फूलना है। किरण बेदी को भी वही आर्थिक नीतियां ढोनी पड़ेंगी जो मोदी उन पर लादेंगे। यह भी तय है कि राष्टीय स्वयंसेवक संघ (आर एस एस) का हिन्दुत्ववादी एजेंडा भी जमकर लागू किये जाने का दबाव रहेगा। यानी किरण बेदी के मुख्यमंत्री बनने की सूरत में वे मात्र एक मुखौटा ही बनकर रह सकती हैं। मुखौटों ने भला कब किसी का विकास किया है?

भारतीय लोकतंत्र के लिये जरूरी है कि मोदी जैसे स्वेछाचारी शासकों पर अंकुश रहे। मोदी सरकार में लाखों का सूट पहनने वाले मोदी कोई अकेले नहीं हैं। आज भाजपा के बड़े नेताओं से लेकर छुटभैयों तक में डिजायनर कपड़े पहनने और पंचसितारा जीवनशैली की होड़ देखी जा सकती है। इस जमात से जनता के दुख-दर्द कम करने की उम्मीद रखना इनके साथ घोर ज़्यादती ही होगी। इनकी पुरानी खड़ताल को अगले लोकसभा चुनाव तक सुनने की मजबूरी से इस देश के नागरिक को रोज़ाना दो-चार होना ही है।

लिहाजा, बेशक आज यह किसी को न भी बताया जा सके कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में कौन जीतने जा रहा है, यह तो बताया जा सकता है कि लोग़ों और लोकतंत्र के हित में सिर्फ़ और सिर्फ़ 'आप' को जीतना चाहिये।

आम आदमी के कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण नहीं रहे

26 जनवरी 2015 को पुणे में 93 वर्षीय इस महान कलाकार ने अन्तिम सांस ली। 'मज़दूर मोर्चा' परिवार की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनका यह पुराना कार्टून दिया जा रहा है। आगामी दिल्ली चुनाव के संदर्भ में यह कार्टून और भी प्रासांगिक लगता है-शासकों के नज़रिये से मतदाता को उसकी हैसियत का भान कराने में।

ख़बर दार

राजपथ पर जन गण मन के पंचसितारा पहरूए...

हर वर्ष की तरह इस बार भी राजपथ पर 26 जनवरी की सैन्य प्रदर्शनी और सिविल झांकियां रंग और उत्साह से भरपूर रहीं। गत सालों के मुकाबले वी आई पी बॉक्स में बैठे सत्ता के पहरूए कुछ ज्यादा ही चमचमा रहे थे। एक तो इस लिये कि उन्हें उधार की आभा देने के लिये अमेरिका से पूंजीशाहों के सबसे बड़े राजनीतिक आका राष्ट्रपति बराक ओबामा स्वयं पधारे थे। दूसरे, पहली बार बतौर प्रधानमंत्री गणतंत्र दिवस समारोह की शोभा बढा रहे नरेन्द्र मोदी का रंग-बिरंगा पंचतारा गेट-अप अलग ही छटा बिखेर रहा था। राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी से लेकर तमाम अन्य मन्त्रियों व विशिष्टजनों पर भी औपनिवेशिक जमाने का रौब-दाब चढा हुआ देखा जा सकता था।

सत्ता के इस दिखावटी ताम-झाम के बीच देश के आम नागरिक की हैसियत कितनी दयनीय रह गयी है, यह भी झांकियों के संयोजन से स्पष्ट हो रहा था। चार दिन पहले पानीपत में मोदी ने 'बेटी बचाओ बेटी पढाओ' के नाम से महिला सशक्तीकरण का ढकोसला शुरू किया था। उसी क्रम में 26 जनवरी की परेड में शामिल सेना एवं सशस्त्र बलों की टुकड़ियों का नेतृत्व महिला अफ़सरों को सौंपा गया। लगता है मोदी ने ठान लिया है कि नारे

लगा कर और दिखावा करके ही महिलाओं के प्रति उनकी सरकार का दायित्व पूरा हो जायेगा। महिला सशक्तीकरण के असली मुद्दों, जैसे सम्पत्ति एवं निर्णय में भागीदारी, विधायिका एवं नौकरियों में 50 प्रतिशत आरक्षण, यौन अपराधों और घरेलू हिंसा से मुक्ति, भ्रूण हत्या व झूठी शान के नाम पर हत्याओं की समाप्ति जैसे आवश्यक कदमों को लेकर मोदी सरकार ने आगे बढने की ज़रा भी इच्छा-शक्ति नहीं दिखाई है।

देश की जनता के साथ सबसे बड़ा मज़ाक रेल विभाग की वह झांकी कर रही थी जिसमें बुलेट ट्रेन को बड़े गर्व से प्रदर्शित किया गया था, और जिसे देख कर मोदी के चहेते रेल मंत्री सुरेश प्रभु ऊंगलियों से विजय चिन्ह बना कर अपनी बांछें बिखेर रहे थे। ध्यान रहे कि मुंबई से अहमदाबाद तक चलने वाली यह ट्रेन कुछ 63000 करोड़ की लागत से बनाई जायेगी। एन इसी समय पडौसी हरियाणा राज्य के हिसार में एक मानवरहित रेलवे क्रासिंग पर ट्रेन से टकरा कर वाहन में सवार एक ही परिवार के 12 लोग़ों की दर्दनाक मौत हो गयी। ध्यान रहे कि देश में ऐसी कुल बारह हज़ार मानव रहीत रेल-क्रासिंग हैं जिन पर हर वर्ष सैंकड़ों दुर्घटनायें होती है और हज़ारों लोग मरते हैं। इन सभी को अंडरपास या ओवर ब्रिज बना कर दुर्घटना रहित करने का कुल खर्च पचास हज़ार करोड़ रुपये आने का अनुमान है। यानी मोदी राजा की जिद के चलते प्राथमिकता बुलेट ट्रेन की है, लोग मरते हैं तो मरते रहें।

नरेन्द्र मोदी को पहले भी नीरो कहा गया था। नीरो यानी रोम का वह सम्राट जो रोम को जलता देखते हुए आराम से बांसुरी बजा रहा था। सन् 2002 में जब गुजरात राज्य साम्प्रदायिक हिंसा की आग में धधक रहा था और मुख्यमंत्री मोदी दंगाइयों को 48 घंटे का अभयदान देकर राजधर्म त्याग चुके थे, तब उन्हें पहली बार नीरो कहा गया था। अब मानवरहित रेलवे क्रासिंगों पर खूनी दुर्घटनाओं का क्रम बढाते हुए वे बुलेट ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहे हैं-यह उन्हें दूसरी बार नीरो का खिताब देने के लिये काफ़ी है।

छाज तो छाज छालनी भी बोली...

रामदेव और रविशंकर ने बाकायदा लिखकर भारत सरकार के पद्म सम्मान 'ठुकरा' दिये ताकि भविष्य के लिये सनद रहे। इस ठुकराने को मीडिया में बाकायदा प्रचारित भी किया गया। दोनों का कहना था कि वे सन्यासी हैं। और एक सन्यासी को पुरस्कार से क्या लेनादेना।

यानी अदा यह कि संतन को कहा सीकरी से काम। पर सच्चाई इसके ठीक विपरीत है। पहली बात तो ये दोनों महानुभाव सन्यासी नहीं व्यवसायी हैं। दोनों का हज़ारों करोड़ का धंधा सरकारी संरक्षण में फ़ल-फूल रहा है। रविशंकर का तो आध्यात्मिक कैम्पों का देश और विदेश में बेहद मुनाफ़े का जाल बिछा हुआ है। जबकि रामदेव का योग कैम्पों के अलावा उपभोक्ता वस्तुओं से मोटी कमाई का सिलसिला सबके सामने है। सरकार और व्यवसायिक मीडिया में इतना भी दम नहीं कि वे इन पाखंडियों के निरे झूठ को चुनौती दे सकें।

पद्म सम्मान को ठुकराने की असली वजह पर पूरी तरह चुप्पी रखी गयी है। दरअसल रामदेव और रविशंकर अपने लिये भारत रत्न की आस लगाये बैठे थे। लिहाजा, जब उन्हें पद्मविभूषण का प्रस्ताव मिला तो वे इस 'अपमान' को पचा नहीं पाये। तभी, दोनों ने अपने पत्र में यह भी जोड़ दिया है कि उनके बजाय अधिक उपयुक्त व्यक्ति को सरकार की ओर से प्रस्तावित पुरस्कार दे दिया जाय।